चलर ही थी। इलाहाबाद जनपद की बारा, बरछना तथा भेजा तहसीलें विंध्य रेंज में पड़ती हैं जहां सिचाई की कोई सुविधा नहीं है तथा जमीन भी समतल बहुत कम है। इन तहसीलों में डी पी ए पी योजना में काफी कार्य हो रहा था किन्तु भारत सरकार से निर्देश हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में 21.3.83 से डी पी ए योजना समाप्त कर दी जाए और कर दी गई है।

दुख इस बात का है कि डी पी ए पी योजना के तहत जो कार्य हो रहे थे वे भी अपूर्ण रह गए हैं। यदि उनको पूर्ण न किया गया तो जो धन व्यय हुआ है वह भी व्यर्थ हो जाएगा।

मेरा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके डी पी ए पी योजना को पुनः इलाहाबाद जनपद में चलाने का आदेश दे दें।

(III) EARLY CONSTRUCTION OF A 'KISAN NIVAS' AT DELHI

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : हमारे देश में सबसे अधिक संख्या किसानों की है। किसान खाद्यान्न पैदा करता है। दूध पैदा करता है। कपास पैदा करता है। अपने पुत्र और भाई देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। सर्वाधिक वोट दे कर सरकार बनाता है। सब से अधिक परिश्रम करता है और सब से कम उत्पादन का उपभोग करता है। संसार में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उसी का हाथ है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने का मुख्य कारण कृषि उत्पादन है। यही नहीं, स्वतन्त्रता के आंदोलन में जेल में भी किसान ही अधिक गए। किसान के पुत्र और भाई पुलिस में अधिक हैं। वे ही देश की व्यवस्था बनाए हुए हैं। जब बेचारा किसान किसान कभी दिल्ली आता है तो उसके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। उसके ठहरने के लिए एक विशाल किसान निवास दिल्ली में बनना चाहिये ताकि वह बेचारा आकर ठहर सके। मेरी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना है कि किसानों के ठहरने के लिए अविलम्ब एक किसान निवास बनवाएं जैसा कि मथुरा नगर में बना हुआ है।

(IV) FINANCIAL ASSISTANCE TO GUJARAT FOR PROPER IMPLEMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY SCHEMES.

SHRI AHMED MOHAMMED PATEL (Broach) : The State Government has undertaken a programme of providing drinking water facilities in problem villages on top priority basis. Out of the total i.e. 9038 problem villages, 3720 villages were provided water supply facilities by 31.3.1980, leaving 5318 villages to be tackled at the beginning of the Sixth Five Year Plan (1980-85).

During the first two years of Sixth Plan i.e. 1980-81 and 1981-82, 1106 villages are covered. This leaves 4212 villages to be tackled within three years (1982-85). The geohydrological conditions in Gujarat have been changed. The district or Kutch is an arid region. Banaskatha and part of North and South Gajarat, and all the districts in Saurashtra region are drought prone areas. Also, the State has a long coastal area. This has created the problem of salinity ingress. Underground sub-soil water level is going deep every year. These geological situations have made the water supply problem more difficult.

Considering all these aspects and price escalation, the funds required to tackle remaining 4212 villages work out to Rs. 102.95 crores. Government of India has been requested to increase the allocation of Rs. 52.60 crores to achieve the target of 5318 villages by the end of Sixth Plan (1980-85). The programme of providing drinking water facilities to the problem villages is a part of the new 20- Point Programme, and the State Government is very keen to achieve the target, as planned. This issue, therefore, requires immediate attention of Central Government, so that drinking water facilities can be provided to the problem villages.

(V) NEED FOR PROPAGATION AND DEVELOPMENT OF THE BAJJIKA LANGUAGE.